

20/4/26

पश्चात्ती पार्श्वे निधि पेरा डूरी 345 फु  
उप. सा. फ. प्राचीणि आस्तिभार डि. 61017  
है विस्तृत निधि शाहिदा डि. गमन  
नं. से दस हो

निधि मुद्रा गमन



अपखण्ड अधिकारी  
सूस्तगढ़ (राज.)

GCMs  
2025/529

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला-श्रीगंगानगर

लखेश्वरी आदि बनाम पुरखाराम आदि

किस्म मुकदमा:-आदेश 39 नियम 2 (ए) सीपीसी

प्रकरण संख्या:- 221/2025

G.C.M.S.-2025/529

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

20.04.2026

उमय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। दोनों पक्षों को सुना गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं० 1 ता 24 के नाम से संयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ के चक 41 पीबीएन खाता नं० 54/91 की कुल 6.072 है० भूमि में प्रार्थीया का 169/6072 हिस्सा खातेदारी भूमि हैं। इसके अलावा इसी चक के खाता नं० 55/40 की 9.727 है० भूमि में प्रार्थी नं० 1 का 1/36 हिस्सा व प्रार्थी नं० 2 का 1012/9727 हिस्सा खातेदारी भूमि हैं। जमाबंदी शामिल पत्रावली हैं। प्रार्थी नं० 1 द्वारा सहीराम पुत्र मलूराम व प्रार्थी नं० 2 द्वारा बृजलाल पुत्र श्री लालूराम से भूमि खरीद की हैं। सहीराम पुत्र मलूराम व बृजलाल पुत्र लालूराम ने घरू बंटवारा शेष संयुक्त खातेदारो के साथ कर रखा था। खरीद के समय प्रार्थी नं० 1 को चक 41 पीबीएन खाता नं० 54/91 प०न० 66/379 कि०न० 15/0.169 है० पासा पूर्वी व इसके अलावा प्रार्थी नं० 1 व 2 को इसी चक 41 पीबीएन खाता नं० 55/40 प०न० 75/376 कि०न० 16 ता 20/1.012 है०, 25/0.017 है० पासा उत्तरी कुल 1.282 है० भूमि का कब्जा सौंपा गया था। जिस पर प्रार्थीगण काबिज हैं। इस भूमि पर न्यायालय द्वारा स्थगन जारी हैं। स्थगन जारी होने के बाद भी दिनांक 22.07.2025 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कि०न० 20 पर जबरन कब्जा कर चावल की फसल काशत कर दी हैं एवं कि०न० 17 से विधूत कनेक्शन नहीं हटा रहें हैं। अप्रार्थीगण द्वारा जानबुझ कर न्यायालय के आदेश एवं गरिमा की अवहेलना की हैं। इसलिये अप्रार्थीगण के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही प्रारम्भ की जावें एवं कब्जा प्रार्थीगण को दिलाया जावें।

अप्रार्थी नं० 2 ने जरिये वकील हाजिर आकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधा अधूरा तथा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के पेश किया हैं साथ ही प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज प्रमाणित नहीं हैं। मात्र प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि हैं। जो कि साक्ष्य में शामिल नहीं की जा सकती। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथमतया: इसी बिन्दू पर खारीज योग्य हैं दूसरा कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित रकबा संयुक्त खाता में हैं। जिसका खाता विभाजन का वाद स० 191/2025 श्रीमानजी के समक्ष विचाराधीन हैं। खाता विभाजन से पूर्व से पूर्व प्रत्येक काशतकार का प्रत्येक ईन्च पर कब्जा माना जाता हैं। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा इसी प्रकार का एक प्रार्थना पत्र पत्रावली नं० 153/25 अनवान लखेश्वरी आदि बनाम ओमप्रकाश आदि में दिनांक 26.11.2025 को पेश किया था।

.....लगातार 2 पर

  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)



अहकाम प्र-आ-इ-अ  
की तामील

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20.04.2026


जिसमें तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि संयुक्त खाता की भूमि में कौन-कौन काश्तकार किस भूमि पर काबिज हैं। यह तथ्य तय किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुनने के बाद दोनों पक्षकारों को विवादित भूमि की मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पांबंद किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र यह प्रार्थना पत्र मिथ्या कथनों के आधार पर बिना किसी ठोस साक्ष्य के विधि विरुद्ध पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 (ए) सीपीसी निरस्त फरमाया जावे।



बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधा-अधूरा है प्रार्थना पत्र के साथ कोई भी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं की गई है। मात्र फोटो प्रति पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा उभय पक्ष के मध्य खाता विभाजन का वाद जैर कार है। खाता विभाजन से पूर्व किसी भी खातेदार को इन नियमों के तहत बैदखल नहीं किया जा सकता है। संयुक्त भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का इन्च इन्च भूमि पर कब्जा माना जाता है। मात्र कहने पर किसी पक्षकार का कब्जा नहीं माना जा सकता है। कब्जा का प्रश्न वादपत्र में दोनों पक्षों की साक्ष्य आने के उपरान्त तय होगा। प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए विचाराधीन है। दोनों पक्षों को विवादित भूमि मौका की यथास्थिति रखने हेतु पांबंद किया गया है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित करने में असफल रहे हैं। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हम निरस्त करना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 (ए) सीपीसी आधा-अधूरा एवं विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त फरमाया जाता है।

निर्णय सरे इजलाश सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़